# नुर्म फेज-2 में शामिल हों बिहार के 55 शहर

**पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो**

बिहार ने केन्द्र सरकार से राज्य के 55 शहरों को नुर्म( ) फेज-2 में शामिल करने की मांग की है। नगर विकास व आवास मंत्री डा. प्रेम कुमार ने कहा कि इन शहरों के विकास के लिए राज्य सरकार मास्टर प्लान तैयार कर रही है। ऐसे में केन्द्र सरकार को मदद देनी चाहिए। वे केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय व नगर विकास व आवास विभाग की ओर से अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फॉर स्माल एंड मीडियम टाउन्स (यूआईडीएसएम) योजना पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे।

## मंत्री ने केंद्र से की मांग

- शहरो के विकास के लिए केन्द्र दे पैसा, आजादी के बाद से उपेक्षित हैं राज्य के शहर
- नगर विकास पर कार्यशाला में केन्द्र व पूर्ववर्ती राज्य सरकारों पर भड़के प्रेम कुमार

मंत्री ने कहा कि नुर्म फेज-1 में राज्य के मात्र दो शहरों पटना व बोधगया को शामिल किया गया।हमने अन्य शहरों को भी इसमें शामिल करने की मांग की थी। पर, ऐसा नहीं हुआ। जबकि, राजस्थान के अजमेर व पुष्कर और झारखंड के टाटा, रांची व धनबाद को इसमें शामिल किया गया है। डॉ. कुमार ने केन्द्र से शहरों के विकास के लिए धन की भी मांग की।

उन्होंने कहा कि शहरों के विकास के लिए अपेक्षित धनराशि नहीं मिलने से कई जगह काम अधूरा है। मंत्री ने कहा कि तकनीकी पेच फंसाने से विकास अवरुद्ध होता है। आजादी के बाद से ही राज्य के शहरों के विकास पर ध्यान नहीं दिया गया। न केन्द्र ने और न पूर्व की राज्य सरकारों ने।इससे तमाम योजनाएं बनाने की जिम्मेवारी सीधे हमारे ऊपर आ गई है। मास्टर प्लान से लेकर सिवरेज व कचरा प्रबंधन की योजनाएं हमारी सरकार ने बनाई है।

सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने कहा कि राज्य सरकार शहरों के व्यवस्थित विकास के लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाकर काम कर रही है। बिडको के एमडी अनुपम कुमार सुमन ने कहा कि शुरुआती परेशानियां दूर हो चुकी हैं। अब शहरों का विकास सकारात्मक दिशा में बढ़ चुका है।

कार्यशाला को शहरी विकास मंत्रालय के निदेशक प्रेम नारायण, सीटीपीओ के एडिशनल चीफ प्लानर केके पोद्दार ने भी संबोधित किया। संचालन संयुक्त सचिव अरविन्द कुमार सिंह ने किया। कार्यक्रम में बिहार व झारखंड से आए कार्यपालक पदाधिकारी व नगर निकाय अध्यक्षों ने हिस्सा लिया।

jetscreenshot

# 55 शहरों के लिए चाहिए 18500 करोड़ रुपये : डॉ प्रेम

**पटना** ■ नगर विकास व आवास मंत्री डॉ प्रेम कुमार ने कहा कि सूबे के 55 शहरों के विकास के लिए 18,500 करोड़ रुपये चाहिए. जेनुरुम-2 के तहत इन योजनाओं की स्वीकृति केंद्र से मिल जाती है, तो इन शहरों की सूरत बदल जायेगी. जिन 55 शहरों के लिए योजनाएं बनायी गयी हैं, उनमें 11 नगर निगम, 42 नगर पर्षद और दो बोधगया और राजगीर जैसे अंतरराष्ट्रीय शहर शामिल हैं. जेनुरुम-एक में बिहार के पटना व गया शहरों को शामिल किया गया था. डॉ कुमार गुरुवार को बिहार-झारखंड के नगर निकायों में सुधार को लेकर बुलायी गयी दो दिवसीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि छोटे व मध्यम आबादीवाले शहरों के लिए राशि तो जारी की गयी, पर कम मिलने के कारण योजनाएं बाधित हो रही हैं. काम पूरा नहीं होने के कारण असंतोष है. उन्होंने बताया कि अधिकारियों की एक टीम को केंद्र सरकार के पास भेजी जायेगी. राजस्थान में अजमेर व पुष्कर के विकास के लिए योजनाएं स्वीकृत की गयी. अब इसी पैटर्न पर बिहार के गया व बोधगया के विकास की योजनाओं को भी स्वीकृति मिलनी चाहिए.